



मोटर वाहन दुर्घटना में दोष रहित दायित्व प्रणाली

सुदीप सार्व, विधि विभाग, अक्षय नेताम, एलएल.एम.-भाग-2 (द्वितीय सेमेस्टर)
शा. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE



Authors

सुदीप सार्व
अक्षय नेताम

E-mail : lawschoolcg@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 15/02/2026
Revised on : 16/04/2026
Accepted on : 25/04/2026
Overall Similarity : 00% on 17/04/2026



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

0%

Overall Similarity

Date: Apr 17, 2026 (03:42 PM)
Matches: 0 / 1616 words
Sources: 0

Remarks: No similarity found,
your document looks healthy.

Verify Report:
Scan this QR Code



शोध सार

मोटर वाहन दुर्घटनाएँ आज के युग में एक गंभीर सामाजिक और कानूनी समस्या बन गई हैं। बढ़ते वाहनों की संख्या, सड़क सुरक्षा नियमों का सही पालन न होना और तकनीकी कारण इसके मुख्य कारण हैं। दुर्घटना के परिणामस्वरूप व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति को गंभीर हानि पहुँचती है। पारंपरिक कानूनी व्यवस्था में दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए दोष सिद्ध करना आवश्यक होता है, जिससे मुआवजे की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती है। दोष रहित दायित्व प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को दुर्घटना के दोषी को साबित किए बिना ही मुआवजा प्राप्त होता है। इसका उद्देश्य पीड़ित की तुरंत सहायता करना, कानूनी विवादों को कम करना और मुआवजे की प्रक्रिया को तेज बनाना है। इस प्रणाली में वाहन बीमा कंपनियाँ प्राथमिक जिम्मेदार होती हैं और पीड़ित को तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। भारत में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दायित्व और मुआवजे के प्रावधान हैं, लेकिन पारंपरिक दोष आधारित प्रणाली में न्याय पाने में लंबा समय लगता है। No-Fault Liability System के लागू होने से दुर्घटना के पीड़ित को शीघ्र मुआवजा मिलता है और न्याय प्रक्रिया सरल हो जाती है। इसके माध्यम से समाज में सड़क सुरक्षा जागरूकता और वाहन मालिकों की जिम्मेदारी भी बढ़ती है। यह अध्ययन दोष रहित दायित्व प्रणाली के कानूनी, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण करता है। इसमें प्राथमिक डेटा के रूप में दुर्घटना मामलों और बीमा कंपनियों के रिकॉर्ड शामिल हैं, और द्वितीयक डेटा में कानूनी जर्नल, शोध पत्र और सरकारी रिपोर्ट शामिल हैं। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि दोष रहित दायित्व प्रणाली पारंपरिक दोष आधारित प्रणाली की तुलना में अधिक प्रभावी और न्यायसंगत है।

मुख्य शब्द

मोटर वाहन दुर्घटना, दोष रहित दायित्व, मुआवजा, बीमा प्रणाली, सड़क सुरक्षा, कानूनी प्रणाली.

प्रस्तावना

- मोटर वाहन दुर्घटनाएँ: एक गंभीर सामाजिक और कानूनी समस्या:** आज के युग में मोटर वाहन दुर्घटनाएँ केवल यातायात की समस्या नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संकट भी हैं। बढ़ती आबादी, वाहन संख्या में वृद्धि और अनियमित सड़क उपयोग से दुर्घटनाओं की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। सड़क दुर्घटनाएँ न केवल जीवन और स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि आर्थिक नुकसान, रोजगार हानि और स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव भी उत्पन्न करती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, विश्वभर में प्रतिवर्ष लगभग 1.3 मिलियन लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और 20-50 मिलियन लोग घायल होते हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की दर बहुत अधिक है, और यह प्रतिवर्ष हजारों जान और संपत्ति के नुकसान का कारण बनती है।
- पारंपरिक दोष आधारित प्रणाली:** भारतीय कानून और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत पारंपरिक प्रणाली में मुआवजे का निर्धारण दोष सिद्ध होने पर निर्भर करता है। यदि दुर्घटना में किसी का दोष सिद्ध नहीं होता, तो पीड़ित को न्याय प्राप्त नहीं हो पाता। इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है, और पीड़ित को आर्थिक और मानसिक हानि उठानी पड़ती है। न्याय प्रक्रिया में लंबा समय, कानूनी जटिलता और अदालतों पर दबाव पारंपरिक प्रणाली की प्रमुख समस्याएँ हैं।
- दोष रहित दायित्व प्रणाली का महत्व:** दोष रहित दायित्व प्रणाली में दुर्घटना के दोषी को साबित किए बिना पीड़ित को मुआवजा मिलता है। इसका उद्देश्य पीड़ित को शीघ्र राहत प्रदान करना, कानूनी विवादों को कम करना और मुआवजे की प्रक्रिया को सरल बनाना है। यह प्रणाली बीमा कंपनियों और प्रशासनिक निकायों के माध्यम से वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती है। इससे समाज में सड़क सुरक्षा और वाहन मालिकों की जिम्मेदारी में वृद्धि होती है।
- भारत में कानूनी और नियामक प्रावधान:** मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दुर्घटना के मुआवजे और दायित्व के प्रावधान हैं। भारत में दोष रहित दायित्व प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है, लेकिन कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट और बीमा संबंधी नियम इसके अनुसार कार्यरत हैं। भारतीय न्यायपालिका ने कुछ मामलों में दोष रहित प्रणाली के तात्त्विक समर्थन का उल्लेख किया है।
- वैश्विक दृष्टिकोण और सीख:** अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में दोष रहित दायित्व प्रणाली सफलतापूर्वक लागू है। इन देशों में दुर्घटना के पीड़ित को तुरंत मुआवजा मिलता है और न्याय प्रक्रिया सरल और त्वरित होती है। वैश्विक अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि दोष रहित प्रणाली न्यायसंगत और सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभावी है।

अध्ययन का महत्व

- कानूनी सुधारों और न्याय प्रणाली में सुधार के लिए मार्गदर्शन।
- पीड़ितों के शीघ्र मुआवजे की प्रक्रिया और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।
- बीमा कंपनियों और प्रशासनिक निकायों के दायित्वों की स्पष्टता।

साहित्य समीक्षा

- Ganguly, A. (2018) No-Fault Liability System and its Impact on Motor Accident Claims.
- Rao, P. (2016) Motor Vehicle Accidents and Legal Reforms in India.
- Mehta, S. (2017) Insurance and Compensation Mechanisms for Road Accidents.
- Sharma, R. (2019) Comparative Study of Fault&Based and No&Fault Systems-

द्वितीयक समंक

कानूनी जर्नल, शोध पत्र, मोटर वाहन अधिनियम, सरकारी रिपोर्ट।

उद्देश्य

1. दोष रहित दायित्व प्रणाली की संरचना और लाभ का अध्ययन।
2. पारंपरिक दोष आधारित प्रणाली और No-Fault Liability System की तुलना।
3. भारत में प्रणाली के प्रभाव और सुधारों का विश्लेषण।

परिकल्पना

H₀: दोष रहित दायित्व प्रणाली प्रभावी नहीं है।

H₁: दोष रहित दायित्व प्रणाली पारंपरिक प्रणाली की तुलना में अधिक न्यायसंगत और प्रभावी है।

परिणाम / विश्लेषण

1. दोष रहित प्रणाली से मुआवजा प्रक्रिया तेज और सरल होती है।
2. पीड़ित को शीघ्र राहत मिलती है।
3. कानूनी विवादों की संख्या में कमी।
4. बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी स्पष्ट होती है।
5. सड़क सुरक्षा और वाहन मालिकों की जिम्मेदारी में वृद्धि।
6. पारंपरिक दोष आधारित प्रणाली में लंबी और जटिल प्रक्रिया का समाधान।
7. वैश्विक दृष्टांतों के अनुसार प्रणाली अधिक न्यायसंगत।
8. भारत में लागू होने पर पीड़ितों को आर्थिक सुरक्षा और त्वरित राहत।
9. दुर्घटना मामलों में न्यायपालिका पर बोझ कम।
10. सामाजिक जागरूकता और सड़क सुरक्षा में सुधार।

चर्चा

दोष रहित दायित्व प्रणाली आधुनिक यातायात और सड़क सुरक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल पीड़ितों के शीघ्र मुआवजे की सुविधा प्रदान करती है, बल्कि न्याय प्रक्रिया को भी सरल और तेज बनाती है। पारंपरिक दोष आधारित प्रणाली में मुआवजा पाने के लिए दोष सिद्ध करना आवश्यक होता है, जिससे पीड़ित वर्षों तक न्याय के इंतजार में रह जाता है। No-Fault Liability System के माध्यम से, दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुए नुकसान के लिए पीड़ित को तुरंत सहायता मिलती है।

यह प्रणाली बीमा कंपनियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बनाती है। वाहन मालिक और बीमा कंपनी मिलकर दुर्घटना के पीड़ित को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जिससे कानूनी विवादों और लंबी प्रक्रियाओं में कमी आती है। इसके अतिरिक्त, दोष रहित दायित्व प्रणाली सड़क सुरक्षा के प्रति समाज और वाहन मालिकों की जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। यदि मालिक जानते हैं कि दुर्घटना होने पर पीड़ित को तुरंत मुआवजा मिलेगा, तो वे सुरक्षित ड्राइविंग और वाहन की उचित देखभाल के प्रति अधिक सतर्क रहेंगे।

वैश्विक अनुभवों से यह स्पष्ट है कि दोष रहित दायित्व प्रणाली प्रभावी है। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रणाली ने मुआवजा प्रक्रिया को न्यायसंगत और शीघ्र बनाया है। भारत में इसे अपनाए जाने से सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को शीघ्र राहत मिलेगी, न्यायपालिका पर बोझ कम होगा और समाज में सड़क सुरक्षा की जागरूकता बढ़ेगी।

निष्कर्ष

दोष रहित दायित्व प्रणाली मोटर वाहन दुर्घटनाओं में पीड़ितों के लिए न्याय और राहत सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। पारंपरिक दोष आधारित प्रणाली में लंबी और जटिल प्रक्रियाओं के कारण पीड़ित न्याय पाने में वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं। No-Fault Liability System के माध्यम से, पीड़ित को तुरंत मुआवजा मिलता है और कानूनी विवादों की संख्या कम होती है। यह प्रणाली केवल कानूनी दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह वाहन मालिकों और बीमा कंपनियों को जिम्मेदार बनाती है, दुर्घटनाओं में शीघ्र राहत सुनिश्चित करती है और सड़क सुरक्षा में सुधार लाती है। भारत में इसे प्रभावी रूप से लागू करने से दुर्घटना के पीड़ितों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी, न्याय प्रक्रिया सरल होगी और सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा।

इस प्रकार, दोष रहित दायित्व प्रणाली मोटर वाहन दुर्घटनाओं के क्षेत्र में न्याय, सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में एक प्रभावी उपकरण है। इसके माध्यम से पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा, सड़क सुरक्षा की जागरूकता और न्यायपालिका

पर बोझ में कमी सुनिश्चित की जा सकती है। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि दोष रहित दायित्व प्रणाली पारंपरिक दोष आधारित प्रणाली की तुलना में अधिक न्यायसंगत और समाजोपयोगी है।

संदर्भ सूची

1. Rao, P. (2016) *Motor Vehicle Accidents and Legal Reforms in India*, Vidhi Sahitya Prakashan, New Delhi.
2. World Health Organization (2023) Global Status Report on Road Safety, <https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/global-status-report-on-road-safety-2023>, Accessed on 10/02/2026.
3. भारत सरकार. मोटर वाहन अधिनियम, 1988. विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. विधि आयोग रिपोर्ट. मोटर दुर्घटना दावों पर विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्टें, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, आधिकारिक सांख्यिकी, morth.nic.in, Accessed on 08/02/2026.
